

भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1568
उत्तर देने की तारीख 04 दिसम्बर, 2024

हिमाचल प्रदेश में 5जी प्रौद्योगिकी

1568. श्री सुरेश कुमार कश्यप:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में 5जी प्रौद्योगिकी शुरू कर दी गई है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बीएसएनएल द्वारा प्रस्तावित 5जी सेवाओं से क्या लाभ प्राप्त हो रहे हैं;
- (ग) यदि नहीं, तो इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और
- (घ) 5जी स्पेक्ट्रम सेवाओं के अंतर्गत कुल कितनी जनसंख्या को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) और (ख) हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में 5जी सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। इसके अलावा देश भर के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 5जी नेटवर्क शुरू किए गए हैं और वर्तमान में देश के 783 जिलों में से 779 जिलों में 5जी सेवाएं उपलब्ध हैं। दिनांक 31 अक्टूबर 2024 तक, देश भर में 4.6 लाख से अधिक 5जी बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) संस्थापित किए जा चुके हैं जिनमें हिमाचल प्रदेश में स्थापित 4,256 बीटीएस शामिल हैं।

5जी सेवाओं के लाभों में पिछली 4जी मोबाइल प्रौद्योगिकी की तुलना में उच्चतर पीक डेटा दरें, कम लेटेंसी और उच्चतर स्पेक्ट्रम कार्यक्षमता शामिल हैं।

(ग) और (घ) सरकार ने 5जी सेवाओं के प्रसार के लिए कई पहल की हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- i. नीलामी के माध्यम से मोबाइल सेवाओं के लिए पर्याप्त स्पेक्ट्रम का आवंटन।
- ii. वित्तीय सुधारों के परिणामस्वरूप समायोजित सकल राजस्व (एजीआर), बैंक गारंटी (बीजी), ब्याज दरों और जुर्माना युक्तिसंगत हो गए हैं।
- iii. स्पेक्ट्रम के कुशल उपयोग के लिए स्पेक्ट्रम शेयरिंग, व्यापार और सरेंडर की अनुमति दी गई है।
- iv. एसएसीएफए (रेडियो फ्रीक्वेंसी आवंटन संबंधी स्थायी सलाहकार समिति) क्लीयरेंस की प्रक्रिया का सरलीकरण।
- v. दूरसंचार (मार्ग का अधिकार) नियमों की अधिसूचना और पीएम गतिशक्ति संचार पोर्टल लॉन्च करने से आरओडब्ल्यू अनुमतियां को सुव्यवस्थित बनाया गया है और दूरसंचार अवसंरचना की संस्थापना के लिए क्लीयरेंस प्रक्रिया में तेजी आई है।
- vi. स्मॉल सेल और दूरसंचार लाइन की संस्थापना के लिए स्ट्रीट फर्नीचर के उपयोग के लिए समयबद्ध अनुमति के लिए आरओडब्ल्यू नियमों में प्रावधान किया गया है।

हिमाचल प्रदेश में दिनांक 31 अक्टूबर 2024 तक, लगभग 4,256 5जी बीटीएस लगाए जा चुके हैं। 5जी सेल कवरेज की रेंज कई कारकों द्वारा निर्धारित होती है, जिनमें परिनियोजित की जाने वाली फ्रिक्वेंसी बैंड, भौगोलिक भू-भाग की स्थिति, विकिरण शक्ति और क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व शामिल हैं। इसके अलावा यह अनुमान लगाया गया है कि हिमाचल प्रदेश राज्य में 60% से अधिक आबादी 5जी मोबाइल सेवाओं द्वारा कवर कर ली गई है। दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) हिमाचल प्रदेश सहित पूरे देश में 5जी नेटवर्क को लगातार बढ़ा रहे हैं।
